विश्व बैंक

संपर्क-सूत्र: *दिल्ली में:* गीतांजलि चोपड़ा (91-11) 2461-7241
ई-मेल: gchopra@worldbank.org

वाशिंगटन में: करीना मानासेह (202) 473-1729
ई-मेल: kmanasseh@worldbank.org

विश्व बैंक ने भारत के लिए सहायता-संबंधी नई रणनीति लांच की

वाशिंगटन, 26 अगस्त, 2004 — विश्व बैंक ग्रुप[1] की भारत की सहायता-संबंधी नई रणनीति में 3 बिलियन अमरीकी डालर तक के लेंडिंग कार्यक्रम की परिकल्पना की गई है, जिससे विश्व के निर्धनतम नागरिकों में से कुछ पर पड़ने वाले विकास कार्यों के प्रभाव में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि होगी। उक्त धनराशि पहले से अधिक है।

बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल ने आज वर्ष 2005-2008 की अवधि के लिए रणनीति पर विचार-विमर्श किया। यह रणनीति एक ऐसा दस्तावेज़ है, जिसमें विकास-संबंधी अपने लक्ष्य प्राप्त करने में भारत की मदद करने के बारे में बैंक के रणनीतिक दृष्टिकोण का वर्णन और इसके तहत मुहैया कराई जाने वाली सहायता के स्तर की ओर इंगित किया गया है।

भारत की अर्थव्यवस्था के आकार और इसकी आर्थिक व सामाजिक विकास-संबंधी आवश्यकताओं को देखते हुए विश्व बैंक ग्रुप के संसाधन कम हैं। *नॉलेज* (ज्ञान, जानकारी) और *लेंडिंग* (ऋण) समेत बैंक के विविध संसाधनों को भारत की सहायता करने के लिए इस्तेमाल करना देश की सहायता-संबंधी रणनीति *(कंट्री स्ट्रैटेजी)* के लिए प्रमुख चुनौती है। ऐसा करने से भारत को विश्व के कुछ एक निर्धनतम नागरिकों के रहन-सहन में सुधार करने, इसे उन्नत बनाने तथा इस सहस्राब्दि के लिए नियत विकास-संबंधी लक्ष्य प्राप्त करने के निकटतर पहुंचने में मदद मिलेगी।

हाल के वर्षों में भारत ने तेज़ी से प्रगति की है और इसकी उल्लेखनीय आर्थिक उपलब्धियों से 1990 के दशक के दौरान लाखों लोगों को निर्धनता से उबारने में मदद मिली है। लेकिन, अभी भी विश्व के एक-चौथाई से अधिक निर्धन एक अरब से अधिक की आबादी वाले इस विशाल देश में रहते हैं तथा उनकी औसत आमदनी बहुत कम है।

----

1. विश्व बैंक ग्रुप में *इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवेलपमेंट (आईबीआरडी)*, *इंटरनेशनल डेवेलपमेंट एसोसिएशन (आईडीए)*, *इंटरनेशनल फाइनेंस कार्पोरेशन (आईएफसी)* तथा *मल्टीलेटेरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी (एमआईजीए)* शामिल हैं। ''बैंक'' शब्द का तात्पर्य *आईबीआरडी* और *आईडीए* से है।

कुछ एक महत्त्वपूर्ण सूचकांकों में थोड़ा-बहुत ही सुधार हुआ है। युवा माताओं और पांच वर्ष की आयु तक के बच्चों की उत्तरजीविता *(सर्वाइवल)* की दरें स्थिर बनी हुई हैं, *एचआईवी/एड्स* की बीमारी तेज़ी से फैल रही है और देश में इसके महामारी का रूप धारण कर लेने का ख़तरा पैदा हो रहा है। विशेषकर महिलाओं तथा अन्य कमज़ोर वर्गों को शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक क्षेत्रों में पर्याप्त और समान अवसर सुलभ नहीं हैं। इसके अलावा, भारतीय राज्यों के बीच भी विषमताएं बढ़ रही हैं, जिनके परिणामस्वरूप निर्धनता का भौगोलिक दृष्टि से कुछ ही क्षेत्रों में जमाव हो रहा है।

भारत में विश्व बैंक के कंट्री डाइरेक्टर **माइकेल कार्टर** ने कहा, "इन विषमताओं को देखते हुए भारत की दो तरह की छवि उभरती है। पहली छवि में आर्थिक सुधार और सामाजिक परिवर्तन प्रमुख स्थान लेने लगे हैं और संवृद्धि का लोगों के रहन-सहन पर प्रभाव पड़ा है, उनके लिए अवसर पैदा हुए हैं। दूसरी छवि में, लगता है कि नागरिक सार्वजनिक सेवाओं, रोज़गार के अवसरों और उज्ज्वल भविष्य की संभावनाओं से करीब-करीब वंचित हो गए हैं। भारत की इन दो छवियों के बीच अंतर को दूर करना आज देश के सामने मौजूद सबसे बड़ी चुनौती है।"

रणनीति-संबंधी इस दस्तावेज़ में बताया गया है कि भारत में बैंक ग्रुप द्वारा कार्यों के परिणामों पर पहले से अधिक ध्यान और चयनात्मकता *(सेलेक्टिविटी)* पर ज़ोर दिया जाएगा, जिससे संसाधनों को ऐसे कार्यों पर लगाया जा सके, जिनके लिए सहायता की ज़रूरत है और जहां ये अत्यंत कारगर साबित हो सकते हैं। जानकारी मुहैया कराने वाली सेवाओं के प्रति वचनबद्धता से यह लाभ होगा कि इस तरह की जानकारी को भारतीय संदर्भ में इस्तेमाल किया जा सकेगा।

इस रणनीति में कार्यक्रमों से संबंधित तीन प्राथमिकताओं की पहचान की गई है:

1. सरकार की प्रभावकारिता में सुधार,
2. लोगों और समुदायों को अधिकारिता दिलाने के लिए किए जाने वाले निवेश का समर्थन, और
3. निजी क्षेत्र के नेतृत्व में वृद्धि को बढ़ावा देना।

इन प्राथमिकताओं के अनुरूप बैंक के कार्यक्रम और लेंडिंग का निम्नलिखित क्षेत्रों में विस्तार किया जाएगा:-

- **बुनियादी ढांचा:** सड़कें, परिवहन, बिजली, जल आपूर्ति और सफ़ाई, सिंचाई और शहरी विकास - जिससे गतिशील वृद्धि को बल मिल सके और सेवाओं की डिलीवरी में सुधार हो सके,
- **मानव विकास:** शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, और
- **ग्रामीण रहन-सहन:** इस क्षेत्र में समुदायों के दृष्टिकोणों पर बल दिया जाएगा।

इस सहस्त्राब्दि के लिए नियत विकास-संबंधी लक्ष्य प्राप्त करने की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए सामान्य व्यवस्थाओं के तहत विकास कार्यों में अन्य भागीदारों के साथ मिलकर निवेश करना एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन है।

देश की सहायता-संबंधी रणनीति में भारत के राज्यों के प्रति दृष्टिकोण में भी कुछ महत्त्वपूर्ण परिवर्तन लाने का प्रस्ताव है। 1997 से बैंक ग्रुप की रणनीति में व्यापक सुधार कार्यक्रम चलाने वाले राज्यों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता रहा है। उदाहरण के लिए, विगत अवधि में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश पर ध्यान दिया गया। भारत के तेज़ी से और धीमी रफ़्तार से विकसित होने वाले राज्यों के बीच बढ़ते हुए अंतर की वजह से भी इस दृष्टिकोण में थोड़ा-बहुत परिवर्तन करना ज़रूरी है, जो इस प्रकार है:-

- प्रथम, भारत सरकार तथा अन्य दूसरे भागीदारों के साथ सलाह-मशविरे से बैंक यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि भारत के विशालतम और निर्धनतम राज्य, अगर वे चाहते हैं तो, चहुंमुखी सुधारों के बारे में परस्पर बातचीत करें।

- दूसरे, बैंक उन चार राज्यों — बिहार, झारखंड, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश — के साथ, जिनमें भारत में निर्धनता का अधिकाधिक जमाव होता जा रहा है, विकास की दृष्टि से उपयोगी संबंध स्थापित करने का प्रयास करेगा।

- तीसरे, आशा है कि इस सहस्राब्दि के लिए नियत विकास-संबंधी लक्ष्य प्राप्त करने के प्रयासों को समर्थन देने के उद्देश्य से राज्य-स्तर पर समायोजन *(एडजस्टमेंट)* लेंडिंग-संबंधी कामकाज भी बैंक के कार्यक्रम का एक महत्त्वपूर्ण अंग बना रहेगा।

- चौथे, ''फोकस राज्यों'' (वे राज्य जिन पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है) पर ध्यान देने के बजाय प्रत्येक क्षेत्र के लिए नियत दिशानिर्देशों के आधार पर राज्यों को अधिक व्यापक पैमाने पर *इन्वेस्टमेंट लेंडिंग* की जाएगी। इन दिशानिर्देशों में क्षेत्र-विशेष से संबंधित परिस्थितियों को परिलक्षित करने का प्रयास किया गया है, जो अनुभव के आधार पर परियोजना की सफलता के लिए ज़रूरी हैं।

माइकेल कार्टर ने यह भी कहा कि इस सहस्राब्दि के लिए नियत विकास-संबंधी लक्ष्य विश्व-स्तर पर प्राप्त करने के उददेश्य से इस रणनीति में एक महत्त्वपूर्ण अवधि — वर्ष 2015 तक निर्धनता में आधे की कमी करना — को भी शामिल किया गया है । *''विकास के लिए सर्वोत्तम व्यावहारिक ज्ञान और वित्त मुहैया कराकर भारत की सहायता करना विश्व में निर्धनता कम करने में मदद करने के विश्व बैंक ग्रुप के मिशन का प्रमुख अंग है, जहां विश्व के एक-चौथाई निर्धन रहते हैं।''*

इंटरनेशनल फाइनैंस कार्पोरेशन (आईएफसी) भारत में निजी क्षेत्र को *इक्विटी* व *लोन फाइनैंसिंग*, गारंटियां और तकनीकी सहायता मुहैया कराता रहेगा। इसमें बुनियादी ढांचे में, जिसमें नई सुविधाओं का निर्माण करने की ज़रूरत है, मार्गप्रशस्तकारी निवेश के साथ-साथ उन परियोजनाओं में निवेश करना भी शामिल है, जिन्हें निजी क्षेत्र के निवेशकों की सीमित दिलचस्पी की वजह से तंगी उठानी पड़ रही है। इनमें मझोले आकार के निर्माण उद्योग, कृषि व्यवसाय और घरेलू व विदेशी बाज़ारों में प्रवेश करने वाली कंपनियां भी शामिल हैं।

कार्यक्रमों और इनकी प्राथमिकताओं को बेहतर ढंग से समर्थन देने के लिए विश्व बैंक की ओर से नीति-संबंधी बातचीत, विश्लेषण, तकनीकी सहायता और परामर्शदात्री सेवाओं पर नए सिरे से ध्यान दिया जाएगा। इस रणनीति में राष्ट्रीय महत्त्व के मुद्दों पर पहले से अधिक विश्लेषणात्मक कार्य करने के साथ-साथ मांग पर आधरित बैंक की प्रतिक्रियाओं *(रेस्पांस)* को सुदृढ़ बनाना भी शामिल है।

इस रणनीति को तैयार करने में एक वर्ष से अधिक का समय लगा और इस अवधि के दौरान सरकार तथा संबंधित मंत्रालयों के साथ काफी विचार-विमर्श किया गया। सलाह-मशविरे की चरणबद्ध और सतत प्रक्रिया के जरिए बैंक के प्रतिनिधियों ने नागरिकों, मीडिया और निजी क्षेत्र के विचारों की जानकारी भी ली।

अधिक जानकारी के लिए निम्न वेबसाइट देखें:
http://www.worldbank.org/indiastrategy